बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 126

दोयम दर्जा सही नहीं

तत्कालीन बंबई में शराबबंदी का एक दौर ऐसा भी था जब केवल विदेशियों को होटल के बार में बैठकर पीने की अनुमति थी। उस दौरान एक हास्य स्तंभकार ने अपनी काल्पनिक पत्नी के बारे में लिखा कि वह एक महंगे होटल के बार में गई और उसने वहां एक ड्रिंक मंगाई। जब उससे कहा गया कि केवल विदेशियों को ही ड्रिंक पेश की जाएगी तो उसने एक ऐसा सवाल किया जिसका कोई जवाब नहीं था। उसने पूछा, आखिर यह देश है किसका?

हर बार जब कोई यह कहता या लिखता है कि विदेशियों को कर दर में रियायत मिलनी चाहिए या उनके लिए कारोबारी प्रक्रिया बेहतर होनी चाहिए, निवेश के लिए विशेष अवसर या इन्वेस्टमेंट एन्क्लेव होने चाहिए, वरना वे अपने डॉलर कहीं और निवेश कर देंगे तो हमें भी यही सवाल उठाना चाहिए। आम दलील इस प्रकार रहती है: नई ऊंची आयकर दर के कारण विदेशियों को रोजगार देना मुश्किल होगा। या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाजार से दूरी बना लेंगे। या हमें अपने पर्यटन स्थलों को साफ-सुथरा और सुंदर रखना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक जुटा सकें। सवाल है कि केवल विदेशी ही क्यों? हम लोगों का क्या जो यहीं रहते हैं और कर चुकाते हैं? क्या हमें बेहतर कर नियम, स्वच्छ शहर और कस्बे पाने का अधिकार नहीं, जहां हम रहते हैं और काम करते हैं? या फिर भारतीय नागरिकों से केवल इसलिए अलग व्यवहार किया जाए क्योंकि उसके पास कहीं और जाने का विकल्प नहीं है?

भारत अब पहले जैसा आर्थिक बंदीगृह नहीं रह गया है। एक दौर था जब आप देश से आठ डॉलर से अधिक की राशि बाहर नहीं ले जा सकते थे। बाद में उदार विदेश यात्रा योजना के तहत 100 डॉलर की राशि ले जाने की अनुमति दी गई। हमारी हालत पुराने सोवियत संघ जितनी भी बुरी नहीं थी क्योंकि वहां एक सुपर बाजार में केवल पश्चिमी पर्यटक ही खरीदारी कर सकते थे। या फिर चीन, जहां वर्षों तक विदेशी केवल विशेष तौर पर जारी विदेशी विनिमय प्रमाणपत्रों में ही लेनदेन कर सकते थे। भारत समेत तमाम जगहों पर अब खुलापन आ चुका है। आज सही मनोदशा वाली कोई भी सरकार ऐसे नियम थोपने की नहीं सोच सकती। अगर वह ऐसा करती भी है तो ये काम नहीं करेंगे। यह पहले भी कभी कारगर नहीं रहा। स्विस बैंकों तथा अन्य टैक्स हैवन वाले देशों में भारतीयों द्वारा जमा किया गया पैसा, हवा में नहीं आया था। उस वक्त तस्करी आम थी और हवाला कारोबार फल-फूल रहा था। इसमें से कुछ पैसा विदेशों से निवेश के रूप में वापस आता था। एक वक्त ऐसा भी था जब भारतीयों ने भी देश में वापस आना शुरू किया था। इससे घरेलू माहौल में सुधार हुआ। नए निजी अस्पताल और स्कूल बने और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार हुआ। कार, फोन सुविधा और हवाई सेवा आदि सभी बेहतर हुईं।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

इसके बावजूद हाल के वर्षों में अमीर और पेशेवर रूप से सफल भारतीयों ने बाहर का रुख किया है। एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि करीब 1.50 लाख से अधिक भारतीयों ने हाल के वर्षों में दुबई, सिंगापुर और पश्चिमी देशों का रुख किया है। शुरुआत में वे कर के आतंक से भाग रहे थे। बाद में कारोबार की प्रभावी जगह के बारे में नए नियम आ गए जिन्होंने कई लोगों को उनके निवास के पते में बदलाव के लिए प्रेरित किया। अन्य लोगों ने शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण, स्कूल में दाखिले की मुश्किल और पानी की कमी आदि के कारण अपने रहने की जगह बदल ली। लाखों की तादाद में भारतीयों ने विदेशी डिग्रियां हासिल कीं या भारत में ही उच्च स्तरीय डिग्री हासिल कीं। इससे उन्हें वैश्विक स्तर पर रोजगार मिलना आसान हुआ। लाखों की तादाद में प्रवासी भारतीय अमेरिका, पश्चिम एशिया और अन्य जगहों पर रहते हैं। इससे अन्य लोगों का वहां जाना आसान होता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारतीयों को वांछित आव्रजक मानते हैं। ऐसा चीन के आव्रजकों को संतुलित करने के लिए भी किया जाता है। संक्षेप में कहें तो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में सक्षम तमाम भारतीयों में से कई भारत छोड़ सकते हैं, और छोड़ भी रहे हैं।

हमें नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार करने की जरूरत है जैसे कि उनके पास विकल्प है, भले ही उनमें से अधिकांश के विकल्प न हो। अगर विदेशी कारोबारी कानूनी आश्वस्ति चाहते हैं तो देश के नागरिकों को भी यह चाहिए। कर अधिकारियों से संरक्षण का विचार अच्छा है लेकिन विदेशियों को नियम कायदों से बचने के लिए विशेष दर्जा देना सही नहीं। जो भी किया जाए वह सबके लिए हो। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा ही होना चाहिए।

बिनय सिन्हा

दूर करें दिक्कतें संपूर्ण विफलता के पहले

इससे पहले कि संपर्क और संचार क्षेत्र में हम पूरी तरह नाकाम हो जाएं, हमें समस्याओं के जमीनी हल तलाश करने की आवश्यकता है। इस विषय में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **श्याम पोनप्पा**

देश की व्यापक तस्वीर में सुधार करने के बारे में काफी बातें होती हैं। हमें वास्तव में कुछ जमीनी सफलताओं की आवश्यकता है। भविष्य की सफलताओं की इमारत खड़ी करने के लिए हमें कुछ जमीनी समस्याओं को हल करना होगा। इसके दो उदाहरणों पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं।

पहला है कारोबारी विफलताओं की पहेली: जेट एयरवेज धीमी गति से ठप होने लगी। वह पहले ही दिवालिया हो चुकी है लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी अन्य घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। एक समय देश की सबसे रखूखदार विमानन कंपनियों में से एक रही जेट एयरवेज अकारण ही बैठ गई और ऐसा होने दिया गया। इससे 16,000 से अधिक कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। कंपनी पर करीब 26,000 करोड़ रुपये की देनदारी है। देनदारों और सरकारी एजेंसियों ने कंपनी को चालू रखने के लिए कार्यकारी कदम क्यों नहीं उठाए, उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया की सहायता भी नहीं ली और न ही फाइनैंसिंग का सहारा लिया। क्या वाकई न्यायिक प्रक्रिया निस्तारण को बाधित करती है? कर्जदाता ढुलमुल रह गए, या वे फंसे हुए कर्ज को लेकर मचे हो हल्ले के बीच घबरा गए या फिर अत्यधिक आश्वस्ति इस पतन का कारण बनी? अगर इन सवालों के जवाब तलाशे गए और उचित कदम उठाए गए तो अन्य भारी भरकम फंसे हुए कर्ज के मामलों से निपटने में सहायता मिल सकती है।

दूसरा मामला है दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल और एमटीएनएल की गड़बड़ियों का। सन 1990 से एक के बाद एक सरकारों ने बार-बार यह प्रयास किया है कि इन दूरसंचार कंपनियों को गति प्रदान की जाए। इस दौरान उन्हें वास्तव में सफल बनाने वाला कोई काम नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर उन्हें स्वतंत्र और हस्तक्षेप मुक्त तथा शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता थी जो उन्हें नहीं मिल सका। यही कारण है कि बीएसएनएल का समेकित घाटा करीब 100,000 करोड़ रुपये हो चुका है। यह जेट एयरवेज के घाटे का पांच गुना और एयर इंडिया के मार्च 2018 तक के घाटे का दो गुना है। बुनियादी सेवा क्षेत्र की इन दिक्कतों को दूर करना अहम है क्योंकि इनका रिश्ता सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा हमारे काम आदि सभी क्षेत्रों से है। अगर बीएसएनएल और एमटीएनएल चीजों में रचनात्मक बदलाव ला सके तो इन्हें बचाया जा सकता है।

अगर इस हालात से निपटा जा सका तो हमारी क्षमता से जुड़े गहन गतिरोध दूर होंगे और उत्पादकता में सुधार होगा। संचार और संपर्क सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों को लेकर दशकों से हमारा रुख बहुत गलत रहा है। हमने कभी इसमें जरूरी बदलाव नहीं किए जिसकी परिणति इस प्रकार सामने आई। अब सरकार इस क्षेत्र में करोड़ों की पूंजी डालने जा रही है। इसके अतिरिक्त जमीन और परिसंपत्तियों से भी धन जुटाया जाएगा।

जनहित में क्या है?

बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए उचित लक्ष्य तय किए जाने चाहिए। उन्हें आम जनता के किन हितों का ध्यान रखना है? संचार मंत्री ने गृह और रक्षा के साथ बाढ़ या चक्रवात के दौरान आपदा प्रबंधन जैसे नीतिगत क्षेत्रों का जिक्र किया है। इसके अलावा जिन दो क्षेत्रों का इस्तेमाल किया गया उनके पीछे कोई तर्क नहीं है। कहा गया कि वे राष्ट्रीय परिसंपत्ति और मुफ्त सेवाओं के प्रमुख सेवा प्रदाता हैं। वाणिज्यिक संस्थान के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्पेक्ट्रम साझेदारी संबंधी नीतिगत वक्तव्य आने के बाद नियमन इतने सख्त कर दिए गए कि उसका कोई उपयोग ही नहीं रहा। इसके बजाय नीति निर्माताओं को ऐसे लक्ष्य तय करने चाहिए जो वाकई जनहित में हों।

अब तक हमें भ्रामक और परस्पर विरोधाभासी लक्ष्य देखने को मिले हैं। नीलामी शुल्क और अन्य शुल्क के रूप में सरकार ने काफी धन जुटाया, इस बीच उम्मीद यह की गई कि उचित मूल्य में अच्छी सेवा भी मिलेगी। जाहिर है ऐसे विरोधाभासी लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। सच तो यह है कि उच्च शासकीय शुल्क के कारण नेटवर्कों के पास फंड की कमी हो जाती है और लागत बढ़ जाती है।

लक्ष्य संबंधी सुझाव

इस दिशा में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं:

■ संपर्क सबसे अहम लक्ष्य है। आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में प्रमुख शहरों और समूहों की अहम हिस्सेदारी होती है और वे प्राथमिकता में हैं। इनमें से 35 से 50 बहुत तेजी से विकसित हो रहे होंगे। जबकि अगले 50 ऐसे होंगे जिन पर उनके आकार के कारण ध्यान देना होगा।

उदाहरण के लिए स्वीडन 2025 तक 98 फीसदी आबादी को न्यूनतम एक जीबीपीएस, 1.9 फीसदी आबादी को 100 एमबीपीएस और 0.1 फीसदी को 30 एमबीपीएस की इंटरनेट गति देना चाहता है। परंतु हमारे देश के दूरदराज इलाकों में सड़क, पानी और सफाई के साथ अगर संचार सुविधाएं मिलेंगी तो गतिविधियां और समृद्धि बढ़ेंगी। इससे शहरों पर प्रवासियों का दबाव कम होगा। ऐसे में दीर्घावधि का लक्ष्य हर जगह बेहतर संचार मुहैया कराना होना चाहिए।

■ जनहित का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए किफायती दर पर विश्वसनीय और अच्छी सेवा मुहैया करानी चाहिए। सवाल यह नहीं है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद किया जाए या नहीं बल्कि उनका सही पुनर्गठन करने और नये कौशल से लैसे करने की आवश्यकता है ताकि वे रक्षा, सुरक्षा और जनहित की निगरानी में काम कर सकें।

■ तीसरा, मुफ्त सेवा और अस्थायित्व भरी कीमतों से बाजार को अस्थिर नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने दूरसंचार, विमानन और बिजली क्षेत्र में बार-बार ऐसा किया है। लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा चाहिए, जो जाहिर है सस्ती दर पर नहीं मिलेगी।

■ चौथा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेवाओं में क्षमता और गुणवत्ता की कमी न हो ताकि सार्वजनिक संसाधन बरबाद न हों। ऐसा करने से ही खराब सेवाओं से बचा जा सकता है।

■ अंत में, हमें बुनियादी ढांचे और स्पेक्ट्रम साझेदारी को अपनाना चाहिए। स्वीडन का मॉडल यूरोपीय संघ के साथ भारत के लिए भी अनुकरणीय है। सिंगापुर में कुछ वर्ष पहले तक निजी- सार्वजनिक भागीदारी का मॉडल था जो सिंगटेल द्वारा ओपननेट के अधिग्रहण के बाद समाप्त हुआ। हमें अनिवार्य सक्रिय नेटवर्क साझेदारी की आवश्यकता है जो निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाता समूहों द्वारा संचालित हो।

बीएसएनएल और एमटीएनएल इसमें संरक्षक प्रतिभागी हो सकते हैं। स्टॉकहोम की बुनियादी क्षेत्र की आईटी कंपनी स्टॉकैब की एक रिपोर्ट सेवाप्रदाता निरपेक्ष फाइबर और मोबाइल बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी मुहैया कराती है।

संपर्क की समस्या को हल करना फंसे हुए कर्ज या कृषि क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करने की तुलना में कहीं अधिक सरल हो सकती है।

इंदिरा जैसा जज्बा दिखा पाएंगी उनकी पुत्रवधू?

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

भारत के छठे आम चुनाव 16 मार्च,1977 को संपन्न हुए। स्वर्गीय आर के धवन का कहना था कि उन्होंने ही इंदिरा गांधी को यह खबर दी कि खुद इंदिरा और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गए हैं। उस समय इंदिरा रात का खाना खा रही थीं। धवन के मुताबिक, इतना सुनते ही इंदिरा के चेहरे पर सुकून के भाव दिखे थे। उन्होंने कहा था, 'अब मेरे पास खुद के लिए और परिवार के लिए वक्त होगा।' अगली सुबह होने तक जब सारे परिणाम आ गए तो उन्होंने राष्ट्रपति से आपातकाल खत्म करने की अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया और फिर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। शायद उनकी जिंदगी में यह पहली बार था जब उनके पास न तो कोई काम था, न कोई आमदनी थी और न ही कोई घर था।

उस समय मेरे एक अंग्रेज दोस्त ने लिखा था कि 'क्या इंदिरा अब अपना वक्त पक्षियों को देखने या हिमालय या कश्मीर में बिताएंगी?' लेकिन उन्होंने कहा था, 'हमें भारत से आने वाली खबरों पर नजर रखनी होगी और आज से पांच साल बाद शायद आप एक बार फिर से विशाल बहुमत से सत्ता में लौटेंगी। लोकतंत्र ऐसा ही है।'

इंदिरा के पास लंदन में रहने का विकल्प था और प्रधानमंत्री बनने के पहले वह ऐसा चाहती भी थीं। लेकिन उन्हें यह अहसास भी हो चुका था कि वह भारत छोड़कर नहीं रह सकती हैं। एक पारिवारिक दोस्त ने उनके लिए अपना बंगला खाली कर दिया और वह अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगीं।

सोची-समझी रणनीति के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारी 3 अक्टूबर, 1977 को इंदिरा की गिरफ्तारी के लिए उनके आवास के बाहर जा पहुंचे। यह शाम 4.45 बजे का वक्त था। अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल को सरकार के इस कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इंडिया टुडे पत्रिका में उस घटना से संबंधित दिलचस्प विवरण दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को इस गिरफ्तारी के लिए हरी झंडी देने के साथ एक हिदायत भी दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर इंदिरा गांधी को हथकड़ी नहीं लगानी है। सीबीआई की टीम 12, विलिंग्डन क्रीसेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ चली। अधिकारियों ने इंदिरा के सहयोगी से कहा कि उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री को हिरासत में लेने को कहा गया है और इसके लिए उन्होंने भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं का हवाला भी दिया। उस समय उन्हें शायद ही मालूम था कि गृह मंत्रालय द्वारा बनाई एफआईआर गलत थी। उन अफसरों को करीब दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा और उस दौरान इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी और पुत्रवधू मेनका ने दिल्ली में मौजूद सभी विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों को टेलीफोन पर इसकी सूचना दे दी।

शाम छह बजे इंदिरा गांधी बाहर निकलीं। उनके वकील फ्रैंक एंथनी ने सीबीआई अफसरों से एफआईआर की प्रति की मांग की तो कहा गया कि उन्हें यह प्रति देना जरूरी नहीं है और इंदिरा गांधी को इन आरोपों के बारे में पढ़कर बताया जा चुका है। इंदिरा ने जब खुद पर लगाए गए आरोपों के बारे में सुना तो उन्होंने कहा, 'हथकड़ी कहां है? मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे हथकड़ी नहीं लगाई जाती है।' हथकड़ी को लेकर करीब एक घंटे तक वाद-विवाद होता रहा।

इस दौरान घर के आसपास कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग चुका था और वे लगातार नारे लगा रहे थे। ब्रह्मानंद रेड्डी, कमलापति त्रिपाठी और मोहसिना किदवई जैसे शीर्ष पार्टी नेताओं के चेहरे पीले पड़ चुके थे। आखिरकार इंदिरा एक कार में बैठीं और वह कार उन्हें लेकर चली गई। उसके पीछे राजीव गांधी और संजय गांधी भी अपनी कारों में रवाना हो गए।

सुबह होते ही एफआईआर में खामी को लेकर चरण सिंह की चिंता सही साबित हो गई। गिरफ्तारी के अगले दिन अदालत में पेश किए जाने पर उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दम नहीं था। जनता पार्टी सरकार ने इंदिरा गांधी को जेल भेजने का अपना मकसद पूरा करने के लिए संसद के विशेषाधिकार हनन प्रावधान का सहारा लिया जब दिसंबर 1978 में उन्हें एक हफ्ते के लिए तिहाड़ जेल में डाला गया था। इंदिरा गांधी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जारी बयान में कहा था, 'मैंने अपनी पूरी क्षमता से इस देश और यहां की जनता की सेवा करने की कोशिश की है। मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप चाहे जो भी हों लेकिन यह गिरफ्तारी विशुद्ध राजनीतिक है। मुझे लोगों के पास जाने से रोकने और उनकी नजर में मुझे गिराने की यह एक कोशिश है। हमने जनकल्याण के लिए शुरू किसी भी कार्यक्रम में सरकार को अपना सहयोग देने की बात कही हुई है लेकिन अन्याय और गड़बड़ी देखने के बाद भी हम मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं।'

जिस दिन उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया था तो युवा कांग्रेस के सदस्य होने का दावा करने वाले दो लोगों ने इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को अगवा कर लिया। वह विमान लखनऊ से दिल्ली जा रहा था और उसमें 126 यात्रियों एवं चालक दल के छह सदस्य सवार थे। अपहर्ताओं ने उसे वाराणसी में ही उतरने के लिए बाध्य कर दिया। उनके चंगुल से बच निकले एक विमानयात्री ने बताया था कि वे इंदिरा गांधी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उस दिन देश भर में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान करीब 18,000 कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए थे।

ऐसे में नैशनल हेरल्ड को लेकर चल रहे मामले में अदालत में पेश होने के मुद्दे पर सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया सुनकर अचरज नहीं होना चाहिए। सोनिया ने कहा, 'मैं इंदिरा गांधी की पुत्रवधू हूं। मैं किसी से नहीं डरती।' पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि शाह आयोग के समक्ष पेश हुए अधिकारियों ने आपातकाल लगाने और मौलिक अधिकारों के स्थगन के लिए इंदिरा गांधी को ही जिम्मेदार बताया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही जिम्मेदार बताया था।

कानाफूसी

मुंबई की मोनोरेल

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत से मोनोरेल परियोजना शुरू की थी लेकिन यह अब सफेद हाथी नजर आ रही है। परियोजना को शुरू हुए आठ वर्ष बीत चुके हैं और इसके चलते शहर के मध्य भाग में जाम और सड़क बंद होने का सिलसिला लगातार चल रहा है। अब यह परियोजना बंद होने जैसी ही है। फिलहाल इसका केवल एक रेक चलन में है लेकिन भारी बारिश के कारण उस मार्ग पर भी परिचालन लगातार बाधित हो रहा है। वेतन भत्तों में देरी के चलते कर्मचारी भी सेवा के परिचालन में बहुत अधिक रुचि नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि स्टेशन खाली नजर आते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि चेंबूर से महालक्ष्मी के बीच चलने वाली इस मोनोरेल का इस्तेमाल कौन करता है: जवाब है मुंबई भ्रमण पर आने वाले पर्यटक।

जेटली की तारीफ

गुरुवार को राज्य सभा में बजट पर चर्चा दोबारा शुरू हुई। इस दौरान करीब 40 से अधिक सांसदों ने अपनी बात रखी। इनमें सत्ताधारी भाजपा के कुछ सांसद भी शामिल थे। परंतु शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल को छोड़कर किसी ने भी वित्त मंत्री अरुण जेटली का जिक्र नहीं किया। गुजराल और जेटली दोनों अच्छे मित्र हैं। गुजराल ने कहा कि वह जेटली का योगदान याद करना चाहेंगे जिन्होंने पांच साल पहले अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी स्थिति से उबारा था। गुजराल ने कहा कि जेटली ने राजकोषीय अनुशासन कायम किया और वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का काम किया। अकाली दल के सांसद ने कहा कि वह ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के क्रियान्वयन के लिए भी जेटली को पूरे अंक देना चाहते हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्यगत कारणों से जेटली सक्रिय राजनीति से दूर हैं।

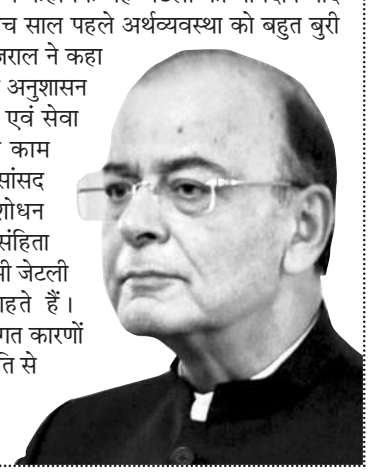

आपका पक्ष

सब्सिडी नहीं खाद पर प्रतिबंध लगाया जाए

किसानों को अब खाद सब्सिडी उनके बैंक खाते में सीधे मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसकी पहल शुरू कर दी है। इसके लिए तीन पहल राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर खाद आपूर्ति, सूचना पट, पीओएस तथा डेस्कटॉप पीओएस संस्करण की शुरुआत की गई है। सरकार के मुताबिक खाद डीबीटी का पहला चरण अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था। इसके तहत पीओएस मशीनों से प्राप्त खुदरा बिक्री आंकड़ों की जांच के बाद सब्सिडी सीधे कंपनियों को दी जाती थी। सरकार जैविक खेती पर अधिक जोर दे रही है जिससे खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम किया जा सके। जैविक खेती में गाय के गोबर तथा गोमूत्र को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाएगा। गाय के गोबर से बने खाद जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरी ओर खाद सब्सिडी किसानों के बैंक खाते में डाले जाने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। जरूरतमंद किसानों को खाद का पैसा सीधे उनके खाते में मिलेगा। लेकिन चोरी करने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। सरकार रसोई गैस की सब्सिडी सीधे खाते में भेजती है लेकिन बाजार में ब्लैक में सिलिंडर बिना सब्सिडी के दाम पर मिलती है और उसकी सब्सिडी जिसके नाम पर गैस कनेक्शन है उसके खाते में चली जाती है। ठीक उसी प्रकार किसान भी खाद खरीद कर अन्य को बेच सकते हैं तथा वह सरकारी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। बहरहाल देश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार को खाद पर सब्सिडी देने के बजाय खाद उत्पादन तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे किसान जैविक खाद इस्तेमाल करने को मजूबर होंगे। इससे पहले वर्ष फसल की पैदावार कम हो सकती है लेकिन अगले वर्ष फसल उत्पादन ठीक हो सकता है।

आनंद शर्मा, नई दिल्ली

सरकार ने किसानों को खाद सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेजने की शुरुआत की है

तपती दिल्ली को मॉनसून का इंतजार

इस साल मॉनसून केरल तट पर चार दिन विलंब के साथ 8 जून को दस्तक दे चुका था। मॉनसून को राजधानी दिल्ली पहुंचने में करीब एक माह का समय लगता है। लेकिन दिल्ली में अब तक मॉनसून नहीं पहुंच पाया है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के पड़ोसी राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मॉनसून पहुंच चुका है लेकिन दिल्ली अभी भी गर्मी से बेहाल है। दिल्ली के चारों ओर मॉनसूनी बारिश हो रही है लेकिन दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सरकारी कागजों में तालाब तो दिखता है लेकिन जमीन पर नहीं। राजधानी अभी भी तप रही है, पानी का संकट बरकरार है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।